RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
सितंबर
19
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

CAG ऑडिटिंग और दक्षता के लिए एआई प्रणाली शुरू करेगा / CAG to launch AI system for auditing and efficiency

संदर्भ:

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अपना खुद का Large Language Model (LLM) विकसित कर रहा है। यह मॉडल ऑडिटरों को दशकों से संचित संस्थागत ज्ञान तक पहुँच प्रदान करेगा। इसके जरिए ऑडिट विश्लेषण में दक्षता और एकरूपता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

CAG का नया एआई सिस्टम:

यह सिस्टम का पहला वर्ज़न नवंबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। इसमें पिछले निरीक्षण (inspection) रिपोर्ट्स को शामिल किया जाएगा, ताकि इसे प्रशिक्षित (trained) किया जा सके।

सिस्टम की क्षमताएँ:

- बड़े डेटा सेट (large datasets) का विश्लेषण करना।
- रिपोर्ट और दस्तावेज़ तैयार करना।
- पैटर्न और जोखिम (patterns & risks) को अधिक सटीकता से पहचानना।
- ऑडिटर्स को विस्तृत और सटीक रिपोर्ट तैयार करने में मदद करना।

डिजिटलीकरण का योगदान:

- केंद्र और राज्यों में व्यापक डिजिटलीकरण से अधिकांश सरकारी एजेंसियों और विभागों का रिमोट या हाइब्रिड ऑडिट संभव होगा।
- इस बदलाव को **risk-based planning**, सुरक्षित एक्सेस (secure access) और **geospatial tools** (जैसे PM GatiShakti) से मज़बूती मिलेगी।
- इससे सबूतों (evidence) और विश्लेषण (analysis) में अधिक एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

पूर्व पहल (Prior Initiatives):

- **Remote Audit Pilots:** GST ऑडिट और तेलंगाना के Stamps & Registration Department में रिमोट कंप्लायंस ऑडिट।
- **Hybrid Audit Demo:** हरियाणा PWD में PAG (Audit) द्वारा हाइब्रिड ऑडिट प्रदर्शन।
- **Paperless Certification:** पश्चिम बंगाल का Virtual Audit System, AuditOnline से जुड़ा।
- **CAG-Connect Portal:** लगभग 10 लाख संस्थाओं को एकीकृत डिजिटल इंटरफ़ेस उपलब्ध कराया गया।

Large Language Models (LLMs)

Large Language Model (LLM) एक प्रकार का **Artificial Intelligence (AI) एल्गोरिद्म** है, जो **deep learning techniques** और बहुत बड़े **data sets** का उपयोग करके टेक्स्ट को समझने, सारांश बनाने, नया कंटेंट जनरेट करने और भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है।

मुख्य विशेषताएँ (Key Features):

1. **Deep Learning का उपयोग:** LLMs असंरचित डेटा का प्रायिक विश्लेषण करते हैं, जिससे वे विभिन्न प्रकार की सामग्री में अंतर समझ पाते हैं।
2. **मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं:** ये मॉडल बिना सीधे मानवीय हस्तक्षेप के कंटेंट को वर्गीकृत और पहचान सकते हैं।
3. **भाषाई समझ:** यह समझने में सक्षम हैं कि अक्षर , शब्द और वाक्य आपस में कैसे काम करते हैं।

एआई और एलएलएम आधारित ऑडिट में चुनौतियाँ

- **डिजिटल परिपक्वता में असमानता:** कई विभागों और स्थानीय निकायों के पास मानकीकृत और उच्च गुणवत्ता वाला डेटा उपलब्ध नहीं है, जिससे एआई-आधारित ऑडिट की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम:** वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा को संभालने से साइबर सुरक्षा खतरों और कानूनी विवादों की संभावना बढ़ जाती है।
- **एआई की विश्वसनीयता और पारदर्शिता की कमी:** LLMs कई बार गलत या भ्रामक परिणाम उत्पन्न करतेहैं और इनके निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती।
- **संस्थागत और कानूनी बाधाएँ:** सरकारी डेटाबेस तक पहुँच के नियम अलग-अलग राज्यों में भिन्न होते हैं, जिससे एकीकृत और सुचारु एआई प्रणाली लागू करना कठिन हो जाता है।

भारत में जेब से स्वास्थ्य व्यय (OOPE) / Out-of-Pocket Health Expenditure (OOPE) in India

संदर्भ:

भारत में स्वास्थ्य वित्तपोषण अभी भी बड़े पैमाने पर घरों द्वारा सीधे चिकित्सा सेवाओं के लिए भुगतान पर निर्भर है। यह जेब से होने वाला खर्च (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE) अक्सर परिवारों को गरीबी और अस्वस्थता के दुष्चक्र में धकेल देता है।

भारत में OOPE (Out-of-Pocket Expenditure) के हालिया रुझान:

National Health Accounts (NHA) के अनुसार, भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय (Total Health Expenditure) में OOPE की हिस्सेदारी 2013-14 के 64% से घटकर 2017-18 में 49% और आगे 2021-22 में 39% रह गई है।

OOPE में कमी के कारण:

1. सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि: 2014-15 में GDP का 1.13% से बढ़कर 2021-22 में 1.84% और 2023-24 में 1.9% तक पहुँचा। हालाँकि National Health Policy (NHP) 2017 का लक्ष्य 2025 तक 2.5% GDP है।

2. आयुष्मान भारत – पीएम-जय (PMJAY): भारत की लगभग 40% आबादी (55 करोड़ लोग, 12 करोड़ परिवार) को लक्षित कर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया।

3. मुफ्त दवा और डायग्नोस्टिक पहल: (National Health Mission के अंतर्गत)

- National Free Drugs Service Initiative
- Free Diagnostic Service Initiative

4. किफायती दवा कार्यक्रम:

- Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP)
- AMRIT Pharmacies

5. स्वास्थ्य अवसंरचना और बजट विस्तार:

- Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) ने प्राथमिक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया।
- स्वास्थ्य बजट 2017-18 के ₹47,353 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹87,657 करोड़ (85% वृद्धि)।
- 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए स्वास्थ्य पर ₹70,051 करोड़ का अनुदान आवंटित किया।

ओओपीई (OOPE) से जुड़ी चिंताएँ और मुद्दे:

1. **एनएसएस (NSS) डेटा पर निर्भरता**
   - एनएचए (NHA) के आकलन मुख्य रूप से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की 75वीं राउंड (2017-18) पर आधारित हैं।
   - यदि बीमारियों की रिपोर्टिंग कम हो या अस्पताल में भर्ती होने की दर घटकर दिखाई जाए, तो ओओपीई के आँकड़े कृत्रिम रूप से कम दिख सकते हैं।
2. **कोविड-19 की अनदेखी**
   - एनएचए ढाँचा महामारी के दौरान हुई गंभीर स्थिति को नहीं दर्शाता।
   - इसका कारण है कि इस समयावधि में एनएसएस डेटा इकट्ठा ही नहीं किया गया।
3. **उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (CES) 2022-23**
   - यह दर्शाता है कि परिवार के उपभोग व्यय में स्वास्थ्य पर होने वाला ओओपीई हिस्सा बढ़ा है।
   - ग्रामीण क्षेत्र: 5.5% ⟶ 5.9% (2011-12 से 2022-23)।
   - शहरी क्षेत्र: 6.9% ⟶ 7.1% (2011-12 से 2022-23)।
4. **सीपीएचएस-सीएमआईई (CPHS-CMIE) डेटा**
   - इसमें 'V' आकार का रुझान दिखता है – कोविड-19 के दौरान ओओपीई में तेज गिरावट और बाद में तीव्र बढ़ोतरी।
   - यह पैटर्न एनएचए के आँकड़ों में पूरी तरह गायब है।
5. **राष्ट्रीय आय खाते (NIA)**
   - इसमें घरेलू स्वास्थ्य व्यय का जीडीपी में हिस्सा लगातार बढ़ता हुआ दर्ज किया गया है।
   - यह प्रवृत्ति एनएचए द्वारा बताए गए गिरावट वाले आँकड़ों के बिल्कुल विपरीत है।

आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) क्या है?

1. **परिभाषा:** ओओपीई का मतलब है वे **प्रत्यक्ष भुगतान (direct payments)** जो व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वयं करते हैं, जिनकी कोई प्रतिपूर्ति (reimbursement) नहीं होती।
2. **इसमें शामिल खर्च:** डॉक्टर की परामर्श फीस, दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक टेस्ट, अस्पताल में भर्ती और सर्जरी, परिवहन व्यय, अनौपचारिक देखभाल आदि
3. **भारत में स्थिति:** भारत में ओओपीई ऐतिहासिक रूप से दुनिया में सबसे अधिक रहा है।
   - यह अक्सर परिवारों को **गरीबी (poverty)** या **कर्ज (debt)** की स्थिति में धकेल देता है क्योंकि स्वास्थ्य खर्च बहुत भारी पड़ते हैं।

अमेरिकी मादक पदार्थों की तस्करी / US Drug Trafficking

संदर्भ:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 देशों को प्रमुख मादक पदार्थ पारगमन या अवैध मादक पदार्थ उत्पादक राष्ट्र के रूप में नामित किया है, जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल हैं।

कुल 23 देश नामित:

- 23 देशों को नामित किया गया, जिनमें शामिल हैं: अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज़, बोलिविया, बर्मा, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, भारत, जमैका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, पेरू और वेनेज़ुएला।
- **असफल राष्ट्र:** निम्नलिखित देशों को "नशीले पदार्थों के खिलाफ ठोस प्रयास करने में पूरी तरह विफल" माना गया: अफगानिस्तान, बोलिविया, बर्मा, कोलंबिया और वेनेज़ुएला।
- **स्पष्टीकरण (Clarification):** अमेरिकी विदेश विभाग (U.S. State Department) ने स्पष्ट किया कि इस सूची में शामिल होना जरूरी नहीं कि किसी सरकार के सहयोग को दर्शाता हो। यह निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक, वाणिज्यिक और आर्थिक कारणों पर आधारित है, जो नशीले पदार्थों के उत्पादन या पारगमन (drug transit/production) को संभव बनाते हैं।

क्यों चिंता में है अमेरिका ?

1. **घरेलू ओपिओइड संकट (Opioid Emergency):**
   - ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को अमेरिका की घरेलू ओपिओइड इमरजेंसी से जोड़ा।
   - अमेरिका में 18 से 44 वर्ष के लोगों की मौत का बड़ा कारण सिंथेटिक ओपिओइड (विशेषकर फेंटेनाइल) बन गया है।
   - ट्रंप ने कहा कि नशीली दवाओं का अवैध व्यापार सीधे तौर पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
2. **ड्रग्स की तस्करी और स्रोत:**
   - **मैक्सिको और कोलंबिया**: यहाँ से बड़ी मात्रा में **कोकीन और हेरोइन** अमेरिका पहुँचती है।
   - **चीन और भारत**: इन्हें **सिंथेटिक ड्रग्स और केमिकल्स** के प्रमुख स्रोत माना जाता है, जिनका उपयोग अवैध दवाओं के निर्माण में होता है।
   - **पाकिस्तान और अफगानिस्तान**: इन देशों से **अफीम और हेरोइन** की तस्करी लंबे समय से अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता का कारण रही है।

गोल्डन क्रिसेंट (Golden Crescent):

- **भौगोलिक क्षेत्र:** अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का overlapping क्षेत्र।
- **महत्व:** यह दुनिया के सबसे बड़े अफीम (Opium) उत्पादन क्षेत्रों में से एक है और ऐतिहासिक रूप से हेरोइन तस्करी का वैश्विक केंद्र रहा है।
- **भारत की चिंता:** पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान की निकटता के कारण भारत हेरोइन तस्करी और क्रॉस-बॉर्डर ड्रग कार्टेल से प्रभावित होता है।

गोल्डन ट्रायंगल (Golden Triangle):

- **भौगोलिक क्षेत्र:** म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमा वाला क्षेत्र।
- **महत्व:** यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम और हेरोइन उत्पादन क्षेत्र है। अब यहाँ धीरे-धीरे सिंथेटिक ड्रग्स (मेथामफेटामाइन) का उत्पादन बढ़ रहा है।
- **भारत की चिंता:** पूर्वोत्तर राज्य (मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड) ढीली सीमाओं (porous borders) और विद्रोही नेटवर्क के कारण नशीली दवाओं की बड़ी मात्रा में आमद का सामना करते हैं।

भारत की कार्रवाई (India's Action):

1. **सख्त कदम और जब्ती (Seizures in 2024)-**
   - सरकार और **NCB** लगातार नशीली दवाओं के नेटवर्क पर शिकंजा कस रहे हैं।
   - वर्ष 2024 में रिकॉर्ड मात्रा में **भांग, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स** जब्त किए गए।
   - **दिल्ली और महाराष्ट्र** कोकीन जब्ती के बड़े केंद्र रहे।
2. **अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रहार-**
   - कई अंतरराष्ट्रीय गिरोहों को पकड़ा गया।
   - दिल्ली में रूटीन चेकिंग के दौरान एक बड़ा **इंटरनेशनल नेटवर्क** उजागर हुआ, जिसका जाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक फैला था।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र / Manufacturing Sector of India

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 'मेड इन इंडिया' उत्पाद खरीदने का आह्वान करते हुए 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया। इसी कड़ी में उन्होंने मध्य प्रदेश के धार ज़िले में देश के पहले पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क की नींव रखी।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector of India)

1. **वर्तमान योगदान**
   - भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा **17%** है।
   - लक्ष्य: इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर **25%** तक पहुँचाना।
2. **प्रमुख फोकस क्षेत्र (Sunrise Sectors)**
   - सेमीकंडक्टर्स
   - नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण (Renewable energy components)
   - मेडिकल डिवाइस
   - बैटरियाँ
   - श्रम-प्रधान उद्योग (Leather, Textile आदि)
3. **विकास और प्रदर्शन (Growth & Performance)**
   - **ASI 2022-23** के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का **आउटपुट 21.5%** बढ़ा।
   - **Gross Value Added (GVA)** की वृद्धि दर **7.3%** रही।
   - प्रमुख क्षेत्र: बेसिक मेटल्स, पेट्रोलियम उत्पाद, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और मोटर वाहन।
   - इन क्षेत्रों का कुल योगदान: **58%** विनिर्माण उत्पादन।
4. **रोज़गार सृजन (Employment Generation)**
   - वर्ष 2022-23 में लगभग **22 लाख नए रोजगार** मिले।
   - प्रमुख राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश – ये राज्य GVA और रोजगार में सबसे बड़े योगदानकर्ता रहे।

भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हाल की उपलब्धियाँ

- **Ease of Doing Business**: 2014 में 142वें स्थान से 2020 में 63वें स्थान पर पहुँचा।
- **वैक्सीन उत्पादन**: भारत दुनिया की लगभग 60% वैक्सीन सप्लाई करता है और कोविड-19 वैक्सीन में वैश्विक निर्यातक बना।
- **वंदे भारत ट्रेनें**: पहली स्वदेशी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें, वर्तमान में 51 ट्रेनें (102 सेवाएँ) चल रही हैं।
- **INS विक्रांत**: पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। 2023-24 में रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ पहुँचा और निर्यात 90 से अधिक देशों तक।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स**: उत्पादन FY17 में 48 अरब डॉलर से बढ़कर FY23 में 101 अरब डॉलर; मोबाइल फोन का सबसे बड़ा योगदान (43%)। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है।
- **साइकिल और बूट्स**: भारतीय साइकिलों का निर्यात यूरोप तक; 'Made in Bihar' बूट्स अब रूसी सेना का हिस्सा।
- **अमूल**: अमेरिका में अपने उत्पाद लॉन्च कर भारतीय डेयरी को वैश्विक मंच पर पहुँचा।
- **टेक्सटाइल उद्योग**: देशभर में 14.5 करोड़ नौकरियाँ सृजित कीं।

भारत का रत्न एवं आभूषण क्षेत्र / Gems & Jewellery

संदर्भ:

अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय हीरों और रत्नों पर 50% का भारी टैरिफ लागू कर दिया है। यह कदम अमेरिकी व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े हीरा कटाई और पॉलिशिंग केंद्रों में से एक है और उसका रत्न एवं आभूषण उद्योग अमेरिकी बाजार पर काफी हद तक निर्भर करता है।

भारत का रत्न एवं आभूषण (Gems & Jewellery) क्षेत्र:

1. **निर्यात पर प्रभाव (Impact on Exports)**
   - भारत के हीरा उद्योग का निर्यात **दसकों के निचले स्तर** पर पहुँच गया है, मुख्य रूप से **चीन में कमजोर मांग** और **अमेरिका में उच्च टैरिफ** के कारण।
   - अमेरिका भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात का लगभग **एक तिहाई हिस्सा** है।
   - **सूरत**, जहां दुनिया के 80% से अधिक कच्चे हीरे कट और पालिश किए जाते हैं, वहाँ ऑर्डर धीरे-धीरे कम हो रहे हैं।
   - कुछ बड़े खिलाड़ी अपने संचालन का हिस्सा **बोत्सवाना जैसे देशों** में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं, जहाँ अमेरिकी टैरिफ केवल 15% है।
2. **आर्थिक महत्व (Economic Significance)**
   - FY 2023-24 में भारत का रत्न और आभूषण निर्यात **US$ 22 बिलियन** रहा।
   - 2027 तक निर्यात **US$ 100 बिलियन** तक पहुँचने का अनुमान।
   - यह क्षेत्र भारत के GDP में **7%** का योगदान देता है।
   - लगभग **50 लाख (5 million) लोग** इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।
3. **मुख्य तथ्य (Key Facts)**
   - FY 2025 में भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात का 33% हिस्सा अमेरिका को गया।
   - भारत दुनिया का शीर्ष हीरा निर्यातक और सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
   - प्रमुख केंद्र: सूरत, जयपुर और मुंबई।
   - प्रमुख निर्यात बाजार: अमेरिका, UAE और हांगकांग।

पैसिफिक एंजल 25 / Pacific Angel 25

संदर्भ:

भारत ने अमेरिका और श्रीलंका के साथ मिलकर **पैसिफिक एंजेल 25** में भाग लिया है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का सबसे बड़ा आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय सहयोग अभ्यास माना जाता है। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन, राहत कार्यों और मानवीय सहायता के क्षेत्र में तीनों देशों के बीच समन्वय और क्षमता निर्माण को मजबूत करने पर केंद्रित है।

पैसिफिक एंजल 25 (Pacific Angel 25)

1. **शुरुआत (Launch):** यह अभ्यास **9 सितंबर 2025** को **कातुनायाके एयर बेस, श्रीलंका** में शुरू किया गया।
2. **उद्देश्य (Objective):** मानवीय सहायता (Humanitarian Assistance) और आपदा राहत (Disaster Relief) संचालन के लिए **क्षेत्रीय तैयारियों को मजबूत करना**।
3. **भागीदारी (Participation):**
   - लगभग **90 अमेरिकी कर्मी** और **120 श्रीलंका एयर फ़ोर्स के सदस्य**।
   - इसके साथ **भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान और मालदीव** के सैनिक और पर्यवेक्षक भी शामिल हुए।
4. **महत्व (Significance)**
   - खोज और बचाव (Search & Rescue) में सुधार।
   - चिकित्सा तैयारियाँ (Medical Readiness) बढ़ाना।
   - हवाई सुरक्षा (Aviation Safety) और इंजीनियरिंग सहायता (Engineering Support) को सुदृढ़ करना।
   - क्षेत्रीय सहयोग और संकट प्रतिक्रिया की गति (Crisis Response Speed) को बढ़ावा देना।

GS FOUNDATION For

UPSC & STATE PSC

- इतिहास
- अर्थव्यवस्था
- भूगोल
- भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

1500x4
~~₹6000/-~~

₹4500/-

- रोज़ाना लाइव क्लासेस
- साप्ताहिक टेस्ट
- क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
- लाइव डाउट सेशन
- रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न

COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
BBK
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Baaten Bazar Ki
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

\+ **(FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)**

FREE

EMI AVAILABLE

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR